GENERAL STUDIES (Module – 4)

निर्धारित समय: तीन घंटे Time allowed: Three Hours	DTVF/19 (N-M)–M–**GS14**	अधिकतम अंक: 250 Maximum Marks: 250

Name: Alok Prasad **Mobile Number:** _____

Medium (English/Hindi): Hindi **Reg. Number:** 17100

Center & Date: M.K.N. 29/July/ **UPSC Roll No.** *(If allotted)*: 8907768

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
*इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं।*
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

1. भारत में सहकारी संघवाद के संबंध में कौन-से संवैधानिक प्रावधान हैं? साथ ही प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिये नीति आयोग द्वारा हाल ही में किये गए कुछ उपायों पर भी चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

What are the Constitutional provisions regarding cooperative federalism in India? Also discuss some of the recent measures taken by NITI Aayog to foster competitive federalism. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सहकारी संघवाद से आशय केंद्र और राज्यों का आपस में सहयोगात्मक सहयोग करते हुए देश के विकास की ओर ले जाने से है।

सहकारी संघवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

1. A-246 तथा 7वी अनुसूची

इसमें तीन सूचियाँ (संघ, राज्य, समवर्ती) है। जिसमें राज्य को राज्यसूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है

② A-268 - केंद्र और राज्यों को अपने अपने अधिकार में कर लगाने का अधिकार है।

③ A-280 - वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य करों का विभाजन करता है। ज्ञातव्य है कि 14 वें वित्त आयोग ने कर अंतरण को बढाकर 42% कर दिया।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

2015 में सहकारी संघवाद ~~हेतु गठित~~ को बढ़ाने हेतु गठित नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाने हेतु निम्न उपाय किए है।

① विभिन्न इंडेक्स → नीति आयोग ने कई इंडेक्स (जैसे - वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, डिजिटल नवाचार इंडेक्स) आदि के माध्यम से विभिन्न राज्यों के बीच एक दूसरे से अच्छा करने हेतु प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया है।

② बॉटम अप एप्रोच के माध्यम से नीति आयोग नीति निर्माण में राज्यों से अधिक सहयोग लेकर प्रतिस्पर्धी संघवाद बढ़ा रहा है।

③ आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से पिछड़े जिलों की बेहतरी हेतु कार्य

स्पष्ट है कि सहकारी संघवाद से एक कदम आगे बढ़ते हुए नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा दिया

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. सोशल मीडिया के युग में आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.) का प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण हो गया है। स्पष्ट कीजिये। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किये गए कुछ उपायों का भी उल्लेख कीजिये। (150 शब्द) 10

Enforcement of Model Code of Conduct (MCC) has become challenging in the era of social media. Elucidate. Also mention some of the measures taken by the Election Commission of India in this regard. (150 words) 10

अभ्यर्थी को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हाल ही हुए (18 वीं लोक सभा) चुनावों में सोशल मीडिया की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। अतः आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन हेतु नई चुनौतियां मिली है।

ध्यातव्य है कि आदर्श आचार संहिता ~~चुनाव आयोग~~ चुनावों के विनियमन करने तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है।

चुनौतियाँ

① ~~चुनाव~~ वोटिंग खत्म होने के 48 घण्टे पूर्व चुनाव प्रचार पूर्णतः निषेध है किन्तु सोशल मीडिया पर इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण होता है।

② सोशल मीडिया के माध्यम से RPA-123 के भ्रष्ट आचरण संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करा पाने संबंधी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

चुनाव आयोग की असमर्थता।

(5) चुनावी प्रचार को लेकर सोशल मीडिया महत्वपूर्ण आयाम है। किन्तु सोशल मीडिया द्वारा प्रचार में खर्च धन संबंधी निर्धारण में चुनौती

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए उपाय

(1) चुनाव आयोग द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया पर चुनाव प्रचार को विनियमित करने की शक्ति की माँग

(2) 48 घण्टे पहले चुनाव प्रचार को सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाये गए हैं

(3) सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले प्रचार के खर्च को उम्मीदवार के खर्च में जोड़ना

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

3. किन परिस्थितियों में एक विधायक को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है? क्या आप सहमत हैं कि इसके लाभप्रद परिणाम के अपेक्षाकृत दुष्प्रभाव अधिक हैं? (150 शब्द) 10

What are the circumstances under which a legislator can be disqualified under anti-defection law? Do you agree that it has caused more harm than good? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

हाल ही में कर्नाटक और गोवा में दल बदल संबंधी कानून की व्यवहार्यता पर प्रश्न उठे।

ध्यातव्य है कि भारत में 1985 से पहले की आया राम गया राम की राजनीति को रोकने हेतु 52 वें संविधान संशोधन (10 वी अनुसूची) के माध्यम से दल बदल कानून लाया गया।

विधायक की अयोग्यता किन-किन संदर्भ में

① अगर कोई निर्दलीय विधायक किसी पार्टी को ज्वाइन करता है।

② किसी पार्टी के 2/3 सदस्यों से कम (91 वे संशोधन) किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो सबकी सदस्यता रद्द।

③ कोई पार्टी विधायक पार्टी से इस्तीफा या सचेतक की व्हिप के विरुद्ध कार्य करता है तो उसकी सदस्यता रद्द

④ सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य द्वारा

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

6 महीने के बाद किसी भी पार्टी में शामिल होने पर सदस्यता रद्द

लाभ

1. आयाराम गयाराम की राजनीति कमी
2. सरकारों का स्थायित्व बढ़ा
3. विधायकों की हार्स ट्रेडिंग (खरीद फरोख्त) कमी

हानि

1. अभी भी सरकार के अस्तित्व पर खतरा
   - उदाहरण - गोवा में 2/3 विधायकों का विलय कांग्रेस में
2. विधायकों के असंतोष प्रकट करने का मौका नहीं देता
3. पार्टी निर्देशों पर कार्य करने की बाध्यता के कारण वह लोगों की आवाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता

~~निष्कर्ष~~ आगे की राह

1. दल बदल कानून संबंधी अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति / राज्यपाल करे (ECI की सलाह से)
   - दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश
2. व्हिप जारी सिर्फ सरकार के अस्तित्व वाले मामलों में हो
   - सरकारिया आयोग की सिफारिश

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

4. राष्ट्रपति और राज्यपालों के अध्यादेश लागू करने की शक्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दे क्या हैं? साथ ही अध्यादेश लागू करने की शक्ति के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु संरक्षोपायों का उल्लेख कीजिये। (150 शब्द) 10

What are the various issues around ordinance making power of President and Governors? Also discuss the safeguards which are in place to prevent misuse of ordinance making power. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

हाल ही में केंद्र सरकार व राज्यसरकारों द्वारा बार-बार अध्यादेश लाने जैसे मुद्दे प्रकट हुए हैं। उदाहरण हेतु - भूमि अधिग्रहण बिल, भगोड़ा अधिनियम आदि

अध्यादेश हेतु संवैधानिक प्रावधान

A-123 → राष्ट्रपति द्वारा

A-213 → राज्यपाल

अध्यादेश की व्यवस्था के पीछे मुख्य उद्देश्य अचानक उपजी हुई परिस्थितियों से निपटने हेतु की गयी थी। किन्तु वर्तमान में इससे जुड़े कई मुद्दे सामने आए हैं।

① एक ही अध्यादेश को बार-बार प्रख्यापित करना। ध्यातव्य है कि कृष्णा कुमार V/S बिहार राज्य मामले में बार-बार अध्यादेश लाने को संवैधानिक धोखाधड़ी कहा था

② शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है इसमें कार्यपालिका का विधायिका के

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

क्षेत्र में अनावश्यक दखल होता है।

③ संसद (लोकसभा, राज्यसभा) को सामना न करने की इच्छाशक्ति का अभाव। लोकतंत्र के मूल उद्देश्य के विरुद्ध

ध्यातव्य है कि अध्यादेश संबंधी चुनौतियों हेतु सुप्रीमकोर्ट द्वारा मुख्यतः 3 बार निर्णय दिया गया

① R.C कूपर केस: अध्यादेश जारी करना सरकार का अनन्य अधिकार नहीं इसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है

② D.C वाधवा और कृष्ण कुमार वाद में भी बार-बार अध्यादेश को लोकतंत्र के विरुद्ध कहा

आगे की राह

① बेहतर होगा कि सरकार बिल लाने के बाद उसके संसदीय समिति के स्तर पर व्यापक विचार विमर्श पर भेजे। तथा असहमतियों को दूर करने का प्रयास किया जाए

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

5. लोकपाल के कर्त्तव्य और शक्तियाँ क्या हैं? क्या लोकपाल का पद सरकार और अन्य, जिनकी जाँच हेतु इसे आज्ञापित किया गया है, से स्वतंत्र है? (150 शब्द) 10

What are the duties and powers of Lokpal? Is the office of the Lokpal independent of the government and others whom it is mandated to scrutinise? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

हाल ही में सरकार द्वारा लोकपाल को गठन किया गया। ध्यातव्य है कि 2013 के इंडिया अगेनस्ट करप्शन मूवमेंट के बाद 2013 में लोकपाल अधिनियम पारित किया गया था किन्तु व्यवहार में लोकपाल स्थापित नहीं हुआ था।

लोकपाल के कर्त्तव्य

① लोकपाल का कर्त्तव्य भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों पर कि न्यायनिर्णयन करना है।

लोकपाल की शक्तियाँ

① किसी भी सरकारी कर्मचारी, PSU में कार्यरत कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी जाँच का अधिकार

② राजनैतिक कार्यपालिका यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी लोकपाल की जाँच के दायरे में

③ स्वतः संज्ञान के आधार पर भी भ्रष्टाचार संबंधी मामले को उठा सकती है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

4. किसी भी जाँच एजेंसी (जैसे · CBI) को निर्देश देने की शक्ति

भ्रष्टाचार रोकना बेहद महत्वपूर्ण है अतः यही कारण है कि लोकपाल जैसी संस्था का सरकार से पूर्ण स्वतंत्र होना की आशा की जाती है। इसकी स्वतंत्रता इस प्रकार है।

① लोकपाल चयन में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप / लोकपाल चयन समिति में विपक्ष का नेता, सुप्रीमकोर्ट के न्यायधीश इत्यादि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

② जाँच की के दायरे में स्वयं सरकार और उसके मंत्री।

③ लोकपाल हेतु अनेक संरक्षण (नियत कार्यकाल, वेतन नियत इत्यादि)

निष्कर्षतः स्पष्ट है कि लोकपाल पर भ्रष्टाचार रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वर्तमान यह निष्पक्ष एवं स्वतंत्रता से काम करे।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

6. भारत में सुशासन के मार्ग में आने वाली कुछ प्रमुख बाधाओं को गिनाइये। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए सुशासन के लिये आवश्यक पूर्व-शर्तों की विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

Enumerate some of the key barriers to good governance in India. Taking cues from these barriers, discuss the necessary pre-conditions for good governance. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

सुशासन से आशय उत्कृष्ट तरीके से किए गए शासन से है। W.B की अवधारणा में सुशासन में निम्न पहलू शामिल किए गए है।

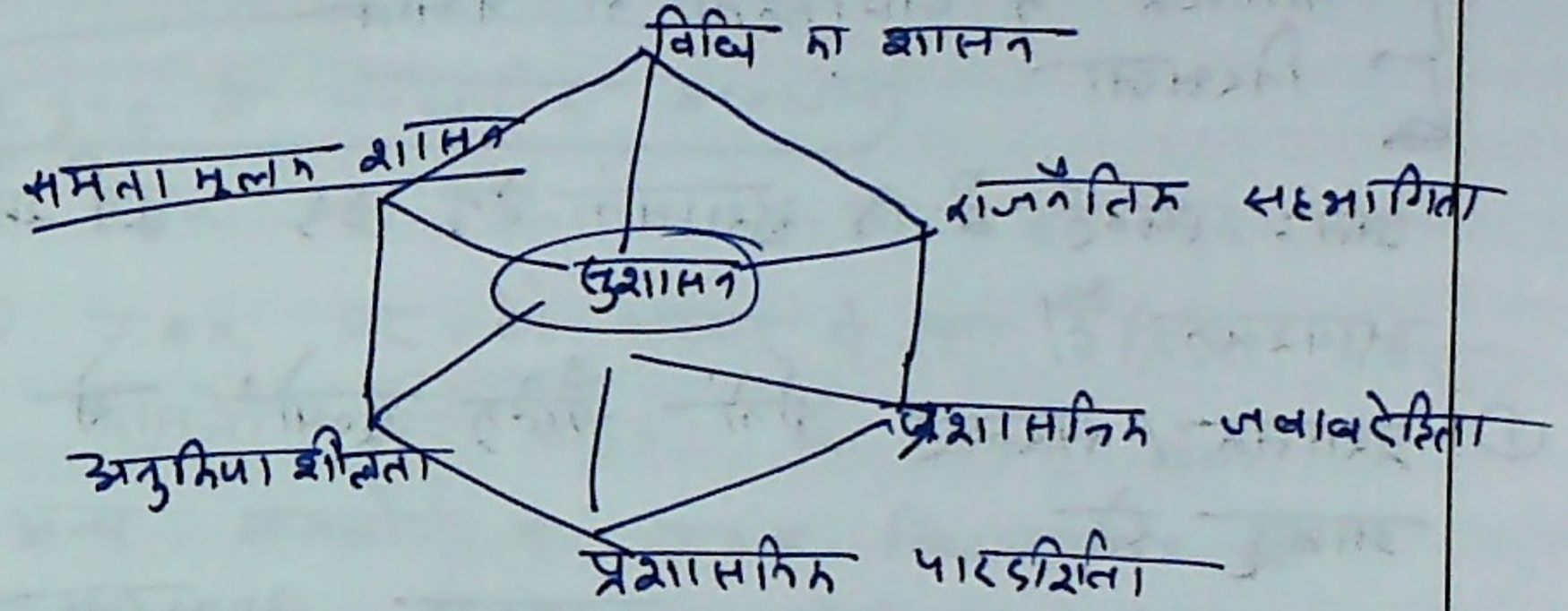

सुशासन के मार्ग में आने वाली बाधाएँ

(1) प्रशासन के स्तर पर
- व्याप्त भ्रष्टाचार
- राजनैतिक - प्रशासन में गठजोड़ (क्लेप्टोक्रेसी)
- प्रशासनिक जवाबदेहिता का अभाव
- प्रशासनिक पारदर्शिता का अभाव (Ex! RTI संबंधी सीमाएँ)
- प्रशासकों की अक्षमता

(2) सरकार के स्तर पर
- (1) व्यापक हित के मुद्दों को उठाने में पीछे जैसे- वंचित वर्ग के अधिकार संबंधी मुद्दे

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(2) भ्रष्टाचार संबंधी प्रतिक्रिया
└ हाल ही में सरकार ने RTI कानून को कमजोर करने की कोशिश

(3) भीड़ हिंसा (विधि के शासन में चुनौती) में सरकार का निष्क्रिय रूप

नागरिकों के स्तर पर
→ नागरिक में जागरूकता का अभाव
→ निरक्षरता

अतः स्पष्ट है कि सुशासन हेतु कुछ पूर्व शर्तें आवश्यक है।

1. प्रशासन / सरकार दोनों नैतिक मूल्यों से आबद्ध रहे
2. जनता के स्तर पर जागरूकता, साक्षरता ताकि अधिकार आधारित दृष्टिकोण स्थापित हो सके
3. स्वतंत्र न्यायपालिका
4. स्वतंत्र निकाय जैसे CVC, CBI, इत्यादि सरकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने की हालत में होने चाहिए

निष्कर्षतः सुशासन न केवल समावेशी विकास बल्कि SDG विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

7. अनुच्छेद 370 की संवैधानिक स्थिति क्या है? वर्तमान परिदृश्य में इससे संबंधित मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

What is the Constitutional status of Article 370? Discuss issues and challenges related to it in the current scenario. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत में अस्थाई अनुच्छेद 370 विचार विमर्श में बना रहता है। ध्यातव्य है कि A-370 के माध्यम से जम्मू & कश्मीर को एक विशेष स्थिति प्राप्त है।

A-370 के संवैधानिक प्रावधान

① J&K पर A-1 & A-370 ही लागू होंगे

② J&K पर केंद्र सरकार से रक्षा, विदेश संचार मामलों पर कानून की सहमति होगी

③ अन्य मामलों में J&K विधानसभा की अनुमति की आवश्यकता होगी।

④ A-370 हटाने हेतु J&K की संविधान सभा की सहमति आवश्यक होगी।

संवैधानिक स्थिति

① J&K उच्च न्यायालय ने A-370 के बारे में कहा था कि A-370 ने भारतीय संविधान में स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया है जिसे हटाना संभव नहीं।

② बाद में पुट्टास्वामी द्वारा उक्त निर्णय को पलट गया।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संबंधित मुद्दे

① जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों से इतर विशेष स्थिति - समानता के सिद्धांत के विरुद्ध

② अनुच्छेद 35(A) संबंधी मुद्दे
- महिला अधिकारों का हनन
- राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक
- अनुच्छेद 14, 15 के विरुद्ध

चुनौतियाँ

① J&K की स्थिति वर्तमान में भी अशांत है वहाँ लगातार आतंकी घटनाएं और उग्रवाद की स्थिति बनी हुई है। अतः A. 370 हटाने इत्यादि से संबंधित निर्णय वहीं की विधान सभा द्वारा ही निर्धारित करना चाहिए।

②

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

8. आपके अनुसार भारत में लोक सेवाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख विकार कौन-से हैं? क्या लोक सेवाओं में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) इनमें से कुछ विकारों का समाधान कर सकता है? (150 शब्द) 10

What do you think are some of the major ailments afflicting civil services in India? Can lateral entry in civil services address some of these ailments? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

हाल ही DOPT द्वारा लोक सेवाओं में लेटरल एंट्री संबंधी प्रस्ताव लाया गया। अत: स्पष्ट है वर्तमान लोक सेवाओं में कुछ विकार मौजूद है।

(1) संरचनात्मक समस्याएँ

- लोक सेवाओं में पद सोपान अत्यंत कठिन

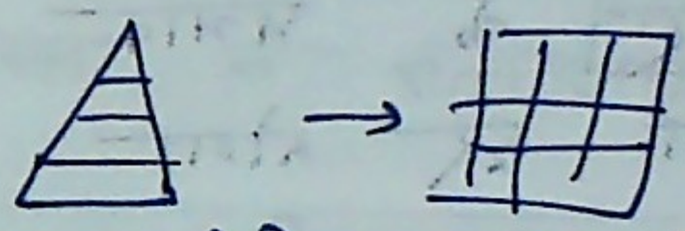

- ग्रेप-वाइन कम्यूनिकेशन इत्यादि की पूर्ण अनुपस्थिति

(2) प्रक्रियागत समस्याएँ

(1) प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का अभाव
(2) तकनीक से जुड़ाव का अभाव, उदाहरण हेतु MZS, PERT इत्यादि का उपयोग किया जा सकता
(3) e-gov के प्रति निष्क्रिय रुख

(3) व्यवहारात्मक विकार

(i) राजनैतिक हस्तक्षेप की समस्या। विशेषत: नियुक्ति, ट्रांसफर संबंधी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. अच्छे कार्य करने वाले सिविल सेवकों हेतु प्रोत्साहन का अभाव

3. अन्य आदि संरक्षणों से प्रशासनिक अक्षमता।

लैटरल एंट्री निम्न रूप में सिविल सेवाओं में सुधार कर सकती है।

(1) वर्तमान सदी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था अतः विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान प्रशासन में नीति निर्माण को सुदृढ़ कर सकता है।

(2) यह नवाचार के अभाव संबंधी समस्या भी दूर होगा।

(3) लैटरल एंट्री: प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनेगा फलतः सिविल सेवाओं में व्याप्त अक्षमता, निष्क्रियता खत्म होगी।

(4) लैटरल एंट्री से आये सिविल सेवकों में संवैधानिक संरक्षण न होने के चलते अकर्मण्यता नहीं होगी।

(5) पदों की कमी पूरी हो सकेगी।

निष्कर्षतः लैटरल एंट्री एक अच्छा विचार है जिसे अपनाकर हम SDG लक्ष्यों की प्राप्ति तथा समावेशी विकास की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

9. एक कमज़ोर विपक्ष सत्ताधारी सरकार को तो खुश कर सकता है परंतु यह लोकतंत्र के हितों को नहीं साधता है। भारत में हालिया आम चुनावों के परिणाम के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिये।

(150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

A weak opposition may make the government of the day happy but it does not serve the cause of democracy. Discuss the statement in light of the outcome of recent general elections in India.

(150 words) 10

हाल ही में 14वीं, 15वीं लोक सभा में प्रमुख विपक्षी दल को 10% सीट भी प्राप्त न हो सकने के चलते विपक्ष के नेता का पद भी प्राप्त न हो सका।

कमजोर विपक्ष से सत्ताधारी सरकार को लाभ

① कमजोर विपक्ष के चलते कार्यपालिका को संसद में किसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता

② सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप के बजाय सत्तावादी स्वरूप की उपस्थिति

③ ~~नीति निर्माण में~~ नीतियों के संबंध में आलोचना करने वाला मजबूत विपक्ष न होने से सरकार अपने अनुकूल नीतियों का निर्माण करती है।

④ —

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

किन्तु विपक्ष की कमजोर स्थिति लोकतंत्र हेतु बेहतर नहीं। जैसे

① सरकार द्वारा कानूनों पर पर्याप्त चर्चा न होना या जल्दबाजी में पास होने के चलते उनमें व्याप्त कमियाँ दूर नहीं हो पाती।

② मजबूत विपक्ष वंचित वर्गों के हितों की आवाज बुलंद करता है। तथा सरकार द्वारा लागू की जा रही नीतियों की आलोचना करता है। ताकि नीतियों को अधिक से अधिक समावेशी बनाया जा सके

③ मजबूत विपक्ष सरकार को गलत मुद्दों पर झुकाने की ताकत रखता है

④ मजबूत विपक्ष सुधारों के क्रियान्वयन हेतु सरकार पर दबाव डालता है जैसे - लोकपाल अधिनियम

निष्कर्षतः लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है कुछ और सुधार भी किए जा सकते है

① शेडो कैबिनेट की उपस्थिति

② सिविल सोसाइटी को मजबूत किया जाए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

10. विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) के निर्धारण हेतु अनुपालित मानदंडों का उल्लेख कीजिये। उनके द्वारा किन मुद्दों का सामना किया जाता है? साथ ही इन मुद्दों के समाधान के लिये सरकार द्वारा किये गए उपायों का भी उल्लेख कीजिये। (150 शब्द) 10

State the criteria followed for the determination of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). What are the issues faced by them? Also mention the measures taken by the government to address these issues. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हाल ही में सरकार द्वारा 75 PVTG जनजातियों को नोटिफाई किया गया।

PVTG के निर्धारण हेतु ढेबर समिति और लोकुर समिति द्वारा निम्न मानदंड बताए गए

1. अत्यधिक सामाजिक पिछड़ापन
2. मूल धारा के विकास से अलाव
3. भौगोलिक अलगाव
4. जन सामान्य से घुलन-मिलन में संकोचग्रस्त
5. अभी भी जीवन यापन हेतु आदिम प्रवृत्तियों पर निर्भर

PVTGs द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दे

1. सामाजिक सेक्टरों का बेहद निम्न विकास
   - शिक्षा के स्तर पर न्यूनतम साक्षरता
   - IMR, MMR का अत्यधिक

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

- उच्च अनुपात
  - ~~गरीबी का उच्च स्तर~~
  - शोषण का शिकार

② आर्थिक पिछड़ापन
- गरीबी का उच्च स्तर
- बेरोजगारी
- ऋणग्रस्तता के शिकार

③ सांस्कृतिक स्तर पर हस्तक्षेप से ग्रस्त
④ विकासात्मक गतिविधियों का लाभ न मिल पाना
⑤ पुनर्वास संबंधी प्रावधान से वंचित

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

① FRA 2006 तथा PESA-1996 के माध्यम से अधिकार सम्पन्न किया जाना
② लघु वन उत्पादों पर स्वामित्व
③ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त & विकास निगम
  - सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद
④ वन बंधु कल्याण योजना

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप, 2019 भारत के शिक्षा क्षेत्र को एक नया आकार दे सकता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(250 शब्द) 15

Draft National Education Policy, 2019 can give a new shape to India's education sector. Critically examine.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

हाल ही में कस्तूरी रंजन समिति द्वारा शिक्षा नीति प्रारूप 2019 प्रस्तुत किया गया। ध्यातव्य है कि वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त अनेक कमियों को दूर करने संबंधी प्रावधान इसमें किए गए हैं।

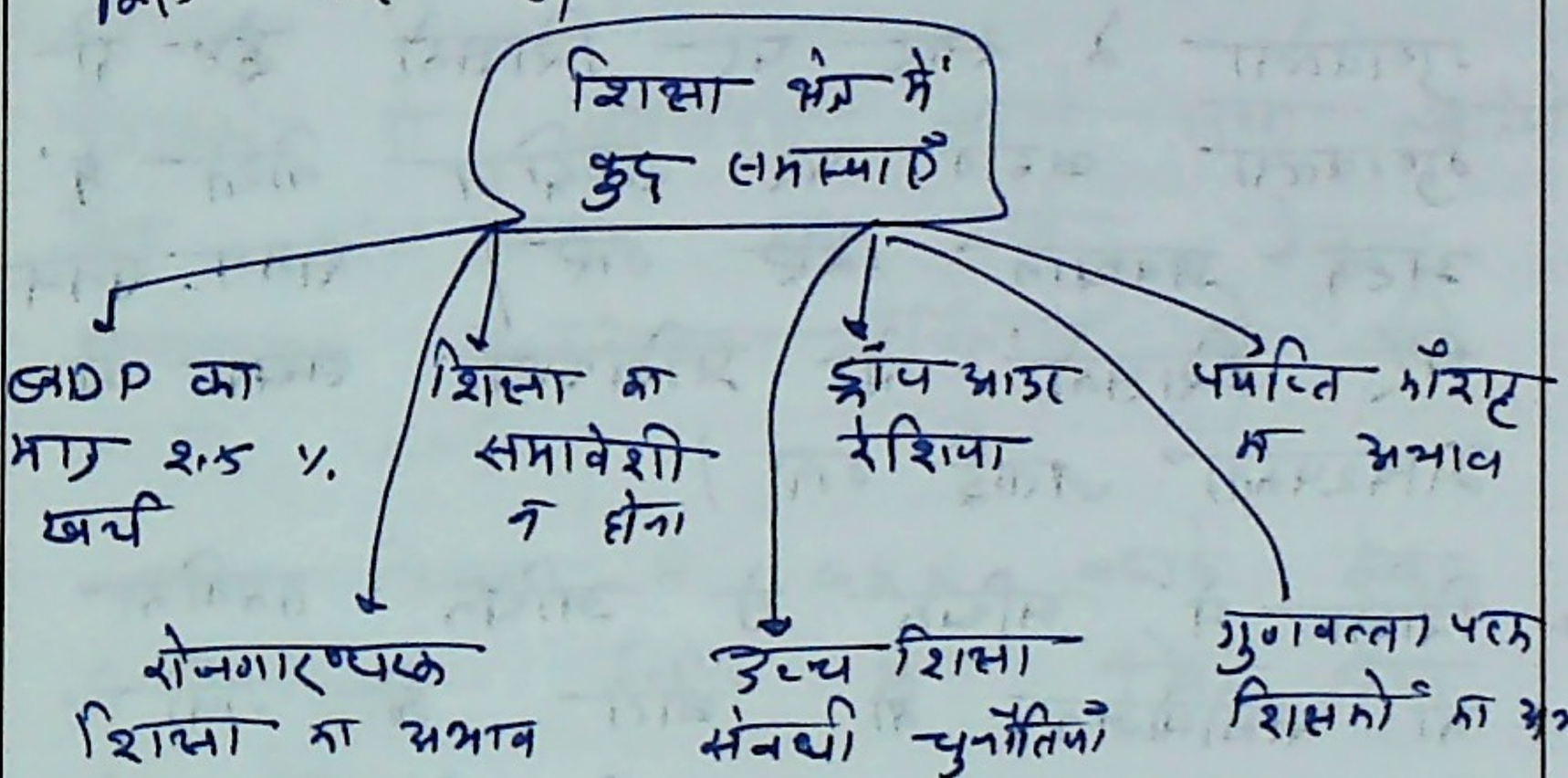

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के व्याप्त सम्पूर्ण कमियों को यथासंभव समाप्त करने की कोशिश की गयी है।

① शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त गुणवत्ता के स्तर पर विशेष कार्य करने की

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

आवश्यकता को दर्शाया गया है। विशेषत: उच्च शिक्षा क्षेत्र का गुणवत्ता हीन होना बेरोजगारी और जनसांख्यिकी लाभांश के दोहन को चुनौतीपूर्ण बना सकता है।

⇒ शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा और उद्योग के लिंकेज की बात की गयी ताकि उद्योगों को आवश्यक कौशल युक्त श्रमबल मिल सके

⇒ गुणवत्ता के स्तर पर शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने पर राष्ट्रीय नीति में अलग प्रावधान किए गए। समय समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता जताई गए।

⇒ शिक्षा में अधिक से अधिक तकनीक का समायोजन की बात की गयी है। ताकि तकनीक के दौर में बच्चों को भी टेक सेवी (Tech savy) बनाया जा सके।

⇒ शिक्षा क्षेत्र में अधिक वित्त उपलब्धता की बात की गयी जोकि GDP के 6% के बराबर हो

⇒ शोध और विकास पर महत्वपूर्ण ध्यान

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

देने की आवश्यकता जताई गयी।

⇒ शिक्षा को मातृभाषा में उपलब्ध कराने तथा शिक्षण सत्र के माध्यम से हिंदी को अखिल भारतीय भाषा बनाने की वकालत भी की गयी।

⇒ स्कूल स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कौशल संवर्द्धन पर बल देने से जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाया जा सकेगा।

⇒ शिक्षा को समावेशी बनाने तथा ड्रॉपआउट कम करने हेतु पर्याप्त अवसंरचना विकास की भी जरूरत जतायी।

⇒ उच्च शिक्षा में GER बढ़ाने हेतु भी शिक्षा नीति में जिक्र किया गया है।

निष्कर्षतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से सर्व समावेशी भारत और जनसांख्यिकी लाभांश से युक्त भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

12. "सामाजिक अंकेक्षण परिकल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को कम करने में सहायता प्रदान करता है।" इस कथन का परीक्षण कीजिये और भारत में सामाजिक अंकेक्षण को प्रणालीबद्ध करने में आने वाली बाधाओं पर भी चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

"Social audit helps to narrow gaps between vision and reality." Examine the statement and also discuss the impediments in institutionalization of social audit in India. (250 words) 15

सामाजिक अंकेक्षण से तात्पर्य नागरिकों द्वारा प्रशासनिक कार्य के ऑडिट और लेखा जोखा करने के अधिकार से है।

हाल ही में सिक्किम में सामाजिक अंकेक्षण को कानूनी रूप दिया गया।

सामाजिक अंकेक्षण की खूबियों को देखते हुए इसे परिकल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को कम करने वाले कारक के रूप में देखा जाता है। जैसे कि

① सामाजिक अंकेक्षण नागरिकों को सशक्त बनाता है। तथा शासन के स्तर पर नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाकर विकेंद्रीकृत शासन की आकांक्षाओं को पूर्ण करता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि चाहिये।

(Candidate must write on this mar

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(2) सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से प्रशासनिक ~~पर~~ पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेहिता में वृद्धि होती है।
जोकि भ्रष्टाचार जैसी कुशासन से मुक्ति दिला सकता है।

(3) बेहतर सामाजिक अंकेक्षण से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो पाता है तथा समावेशी विकास और वंचित वर्ग के हितों को पूरा करने में मदद मिलती है।

(4) सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से पंचायती शासन सशक्त होता है।

(5) भ्रष्टाचार रुकने से परियोजनाओं की वित्त लागत घटती है। फलतः आर्थिक दक्षता बढ़ती है।

हालांकि इसके बावजूद सोशल आडिट में कुछ चुनौतियां व्याप्त है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(1) जनता का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होना

(2) जनता में व्याप्त असाक्षरता (25% भारतीय अभी भी निरक्षर है।

(3) सोशल आडिटिंग की व्यवस्था से प्रशासनिक अकर्मण्यता बढ़ सकती है।

(4) सोशल आडिटिंग संबंधी रिपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों तथा राजनेताओं द्वारा अनुक्रिया न करना। ध्यातव्य है कि 30% प्रशासनिक अधिकारी तथा 50% मामलों में राजनेताओं द्वारा कोई अनुक्रिया नहीं की गयी

निष्कर्षतः सोशल आडिटिंग व्यवस्था के लाभ अत्यधिक है और हानि बेहद कम अतः हम नागरिकों को सशक्त बनाने हेतु सोशल आडिटिंग पर लगातार आगे बढ़ना होगा

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

13. 73वाँ संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के समक्ष आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों को हल करने में नाकाम रहा है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

73rd Amendment Act has failed to address the systemic challenges faced by Panchayati Raj Institutions (PRIs). Critically analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

73rd संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में शासन के तीसरे स्तर की कल्पना को आधार दिया तथा विकेंद्रीकृत शासन की अवधारणा को जमीन पर उतारा गया।

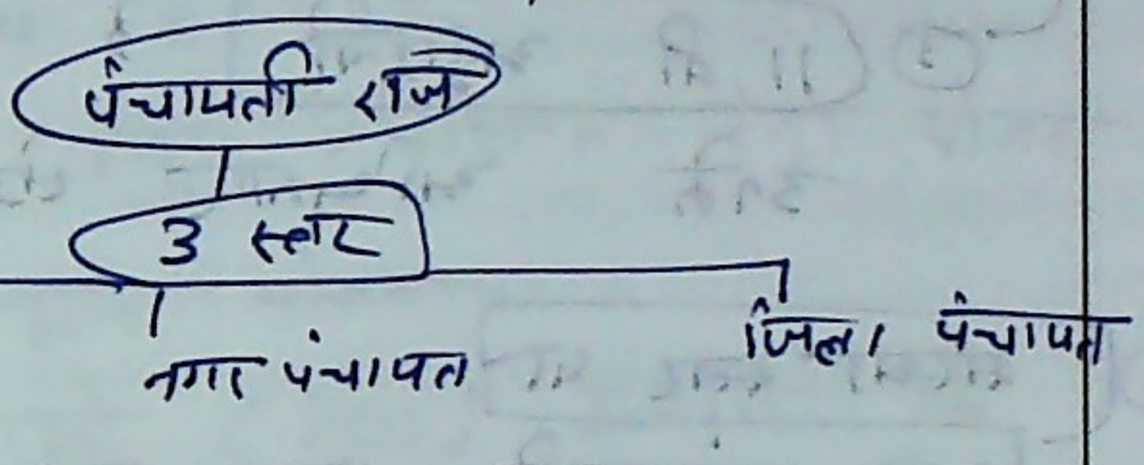

पंचायती राज की अवधारणा बॉटम अप एप्रोच से जुड़ती है किन्तु अभी भी इसके कुछ बाधाएँ व्याप्त है।

① क्रियान्वयन के स्तर पर
- ① भ्रष्टाचार की समस्या अत्यधिक
- ② लोगों में जागरूकता का अभाव
- ③ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने हेतु 33% आरक्षण की व्यवस्था की गयी किन्तु प्रधान पति सिंड्रोम

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

के चलते अभी भी वास्तविक प्रतिनिधित्व की चुनौती

③ वित्त / अधिकारी संबंधी चुनौतियाँ

- ① राज्य सरकारों द्वारा पंचायती स्तर पर पर्याप्त वित्त प्रदान नहीं किया जाता
- ② कर लगाकर वित्त संग्रहण की अत्यल्प शक्ति
- ③ 11 वीं अनुसूची के अधिकांश विषय उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर

③ संस्था स्तर पर

- ① पंचायती स्तर पर ~~सर्व~~ प्रशासनिक तंत्र के विकेंद्रीकरण का अभाव
- ② पंचायत कर्मचारियों की क्षमता विकास संबंधी चुनौतियाँ।
- ③ पंचायत सदस्यों का निरक्षर होना

हालांकि इसके बावजूद पंचायत राज के स्तर पर भारत में कार्य अधिक हुए हैं

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

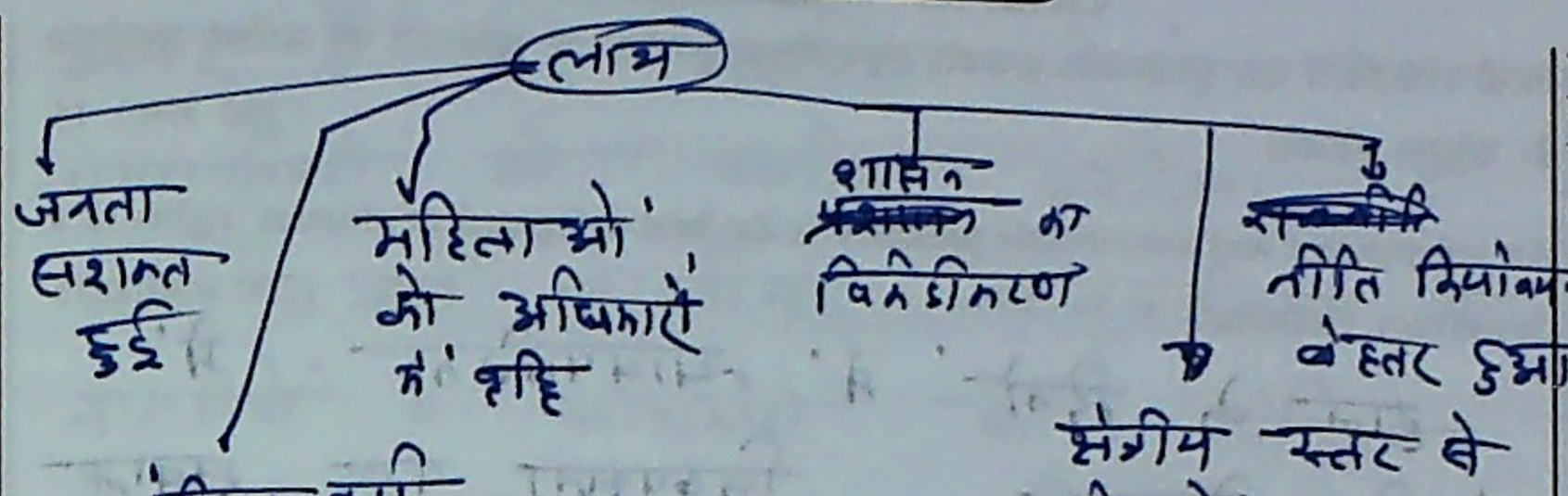

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

इसके बावजूद सरकार कई योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है

① महिला सदस्यों हेतु प्रशिक्षण हेतु योजना

② अन्त्योदय अन्न योजना

③ प्रमुख योजनाओं (PDS) सेवाओं के क्रियान्वयन में पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण

④

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

14. किसी लोकतंत्र में एक स्वतंत्र और जवाबदेह न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों का सर्वोत्तम संरक्षोपाय है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

An independent and accountable judiciary is the best safeguard of citizens' rights in a democracy. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

हाल के दिनों में न्यायपालिका में आंतरिक विभाजन, निष्पक्षता पर सवाल स्वयं न्यायाधीशों द्वारा ही उठाए गए है।

भारत में स्वतंत्र और जवाबदेह न्यायपालिका संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 124 से लेकर A-147 तक मिल जाए है।

स्वतंत्र न्यायपालिका

(1) न्यायाधीशों के चयन की वर्तमान प्रणाली में कार्यपालिका का हस्तक्षेप शून्य के स्तर पर है।

(2) न्यायधीशों को हटाने संबंधी संवैधानिक प्रावधान बेहद कठोर है। दोनों सदनों से विशेष बहुमत की आवश्यकता

(3) न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित

(4) न्यायाधीशों के आचरण की चर्चा संसद में लाने से प्रतिषेध

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

स्पष्ट है कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायाधीशों को पर्याप्त स्वतंत्रता है अतः भारतीय न्यायपालिका है नागरिकों के अधिकारों का सर्वोत्तम संरक्षक है या नहीं इसका विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

① मूल अधिकारों का प्रवर्तन संबंधी अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। ज्ञातव्य है कि न्यायपालिका ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाद में स्वतः संज्ञान से वंचित वर्गों के मूल अधिकारों को संरक्षित किया। यह शक्ति SC को A-32 तथा HC को A-226 के तहत प्राप्त है।

② A-142 के तहत पूर्ण न्याय की शक्ति प्राप्त है। उदाहरण हेतु भोपाल गैस त्रासदी कांड, या हाल ही के कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ~~वंचित वर्गों~~ के पूर्ण न्याय के आधार वंचित वर्गों को सशक्त किया

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation
उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(२) प्रगतिशील निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका नागरिकों को सशक्त करती है
(जैसे - तीन तलाक समाप्ति तथा ~~मंदिर~~ सबरीमाला मंदिर प्रवेश की अनुमति महिलाओं के मौलिक न्याय (A-14, 15, 21) को पुष्ट करती है।

(३) न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के स्तर पर व्याप्त कमियों को पूरा करके नागरिकों को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाई

(४) राजनीतिक स्तर पर राजनीति के अपराधीकरण से मुक्त हेतु न्यायपालिका द्वारा 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करना है बेहतर लोकतंत्र निर्माण हेतु एक कदम ही

(5) MC मेहता मामले (बाल श्रम दिशानिर्देश) विशाखा मामले (कार्यस्थल पर यौन शोषण) तथा MC मेहता (पर्यावरण संबंधी दिशानिर्देश) संबंधी वादों में न्यायपालिका ने नागरिकों को सशक्त किया

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

15. स्वयं सहायता समूह गरीबों को सूक्ष्म वित्त सेवाओं के वितरण के लिये सबसे प्रभावी तंत्र के रूप में उभरे हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Self-Help Groups have emerged as the most effective mechanism for delivery of microfinance services to the poor. Critically examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

स्वयं सहायता समूह से तात्पर्य एक ऐसे समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले समूह से है जो कि एक समान उद्देश्य हेतु संगठित होते है।

ध्यातव्य है कि SHG में 15-20 सदस्य मिलकर एक समूह का निर्माण करते है तथा अपनी बचतो को बैंक में जमा करते है। बदले में बैंक द्वारा उन्हें स्वरोजगार इत्यादि हेतु ऋण प्रदान किया जाता है।

अतः स्पष्ट है कि गरीबो को सूक्ष्म वित्त सेवाओं के वितरण में SHGs द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी। विशेषकर महिलाओ के संदर्भ में।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

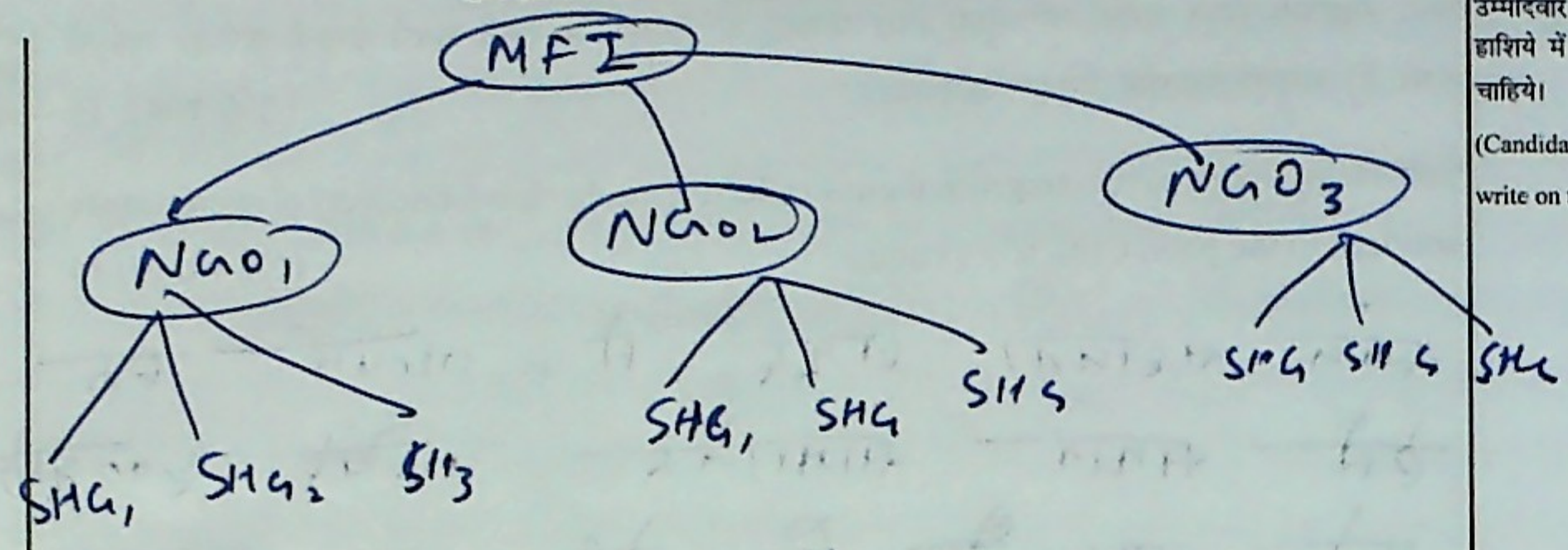

स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीय समावेशन तीव्रता से बढ़ा। वर्तमान में 9.4 करोड़ गरीब SHGs के माध्यम से संगठित हैं जिनमें 4.2 करोड़ महिलाएँ हैं।

गरीबों को इससे अनेक लाभ हुए जैसे

1. स्वरोजगार तथा व्यवसाय करने हेतु ऋण की उपलब्धता हुई।
2. साहूकारों, महाजनों के शोषण से मुक्ति मिली
3. गरीबी निवारण में मदद
4. महिला सशक्तिकरण में मदद मिली → आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी
   → निर्णयन क्षमता ↑
   → पितृसत्तात्मकता कमजोर हुई।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिख[...] चाहिये।
(Candidate must no[...] write on this margi[...]

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

~~सरकार~~ यही कारण है कि सरकार SHGs को लगातार प्रोत्साहित कर रही है।

① SHG Bank लिंकेज प्रोग्राम के माध्यम से बेहद सस्ता ऋण।

② प्रियदर्शिनी योजना – महिला SHG को सुदृढ़ करने हेतु

③ अन्त्योदय योजना —

④ ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना

⑤ नाबार्ड का e-SHAKTI योजना SHG के डिजिटलीकरण हेतु

निष्कर्षत SDG लक्ष्य – 1 (गरीबी निवारण) ~~प्राप्त करने~~ SDG लक्ष्य 5 (महिला असमानता) तथा SDG लक्ष्य 10 (असमानता) ~~समाप्त~~ प्राप्त करने में SHG ग्रुप की महत्ती भूमिका है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. भारत जैसे देश में आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता के लिये संतुलित क्षेत्रीय विकास अति आवश्यक है। 'आकांक्षी ज़िलों के परिवर्तन' कार्यक्रम के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

Balanced regional development is quite essential for economic progress and political stability in a country like India. Discuss the statement in light of 'Transformation of Aspirational Districts' programme. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि
चाहिये।
(Candidate must
write on this mar

पिछले वर्ष नीति आयोग ने 115 जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिला घोषित किया गया।

ध्यातव्य है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का मूल उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। जोकि आर्थिक प्रगति और राजनैतिक स्थिरता हेतु आवश्यक है।

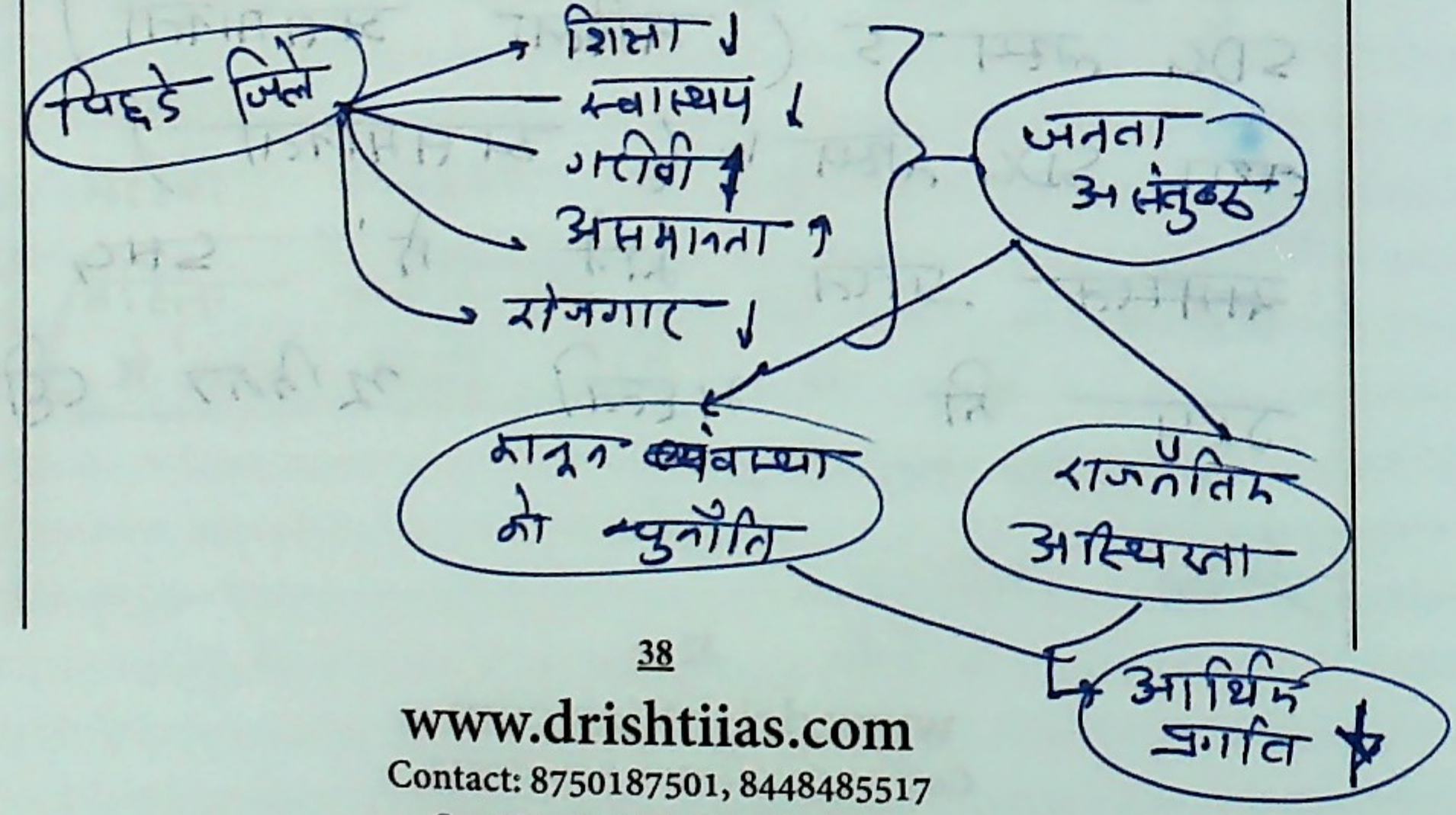

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

आकांक्षी जिला कार्यक्रम में मूलतः पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु निम्न प्रयास किए जा रहे हैं।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

① शिक्षा के स्तर
- साक्षरता दर बढ़ाना
- जागरूकता बढ़ाना
- नागरिकों को अधिकार आधारित ढाँचे से जोड़ना
- रोजगार क्षमता।

② स्वास्थ्य के स्तर पर
- आउट ऑफ पॉकेट खर्च की समस्या का समाधान करना
- गरीबी, कुपोषण से मुक्ति

③ कौशल विकास
- मौसम प्रदान कर रोजगार से जोड़ना
- गरीबी उन्मूलन

④ कृषि
- कृषि को लाभदायक स्थिति में लाने हेतु कृषि अवसंरचना में निवेश बढ़ाना
- कृषि संबंधी मुद्दों को दूर करना

इन जिलों की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

पिछले वर्ष आकांक्षी जिलाओं के स्तर पर बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रतिस्पर्धा भी शुरू की गयी थी

और इस कार्यक्रम में तहत बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। सामाजिक योजनाओं का क्रियान्वयन उत्कृष्ट हुआ है। e-gov, इत्यादि के प्रयोग से नागरिक सशक्तीकरण बढ़ रहा है।

निष्कर्षतः आकांक्षी जिला कार्यक्रम समावेशी विकास का पक्षधर है। और इसके माध्यम से भारत अपने SDG लक्ष्यों विशेषकर SDG-1, (गरीबी) SDG-3 (अच्छा स्वास्थ्य) SDG 4 (अच्छी शिक्षा) को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लि
चाहिये।
(Candidate must
write on this ma

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति को आगे बढ़ाने का एक संभावित मंच है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Shanghai Cooperation Organization (SCO) is a potential platform to advance India's 'Connect Central Asia' policy. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

जून के महीने में SCO ~~का~~ समिट का आयोजन कजाकिस्तान के विश्केक में किया गया।

ध्यातव्य है कि 2017 में भारत SCO का सदस्य बना है। तथा मध्य एशिया से संबंध सुदृढ़ करने हेतु भारत कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति पर कार्य कर रहा है। फलतः SCO की सदस्यता इसमें मददगार हो सकती है।

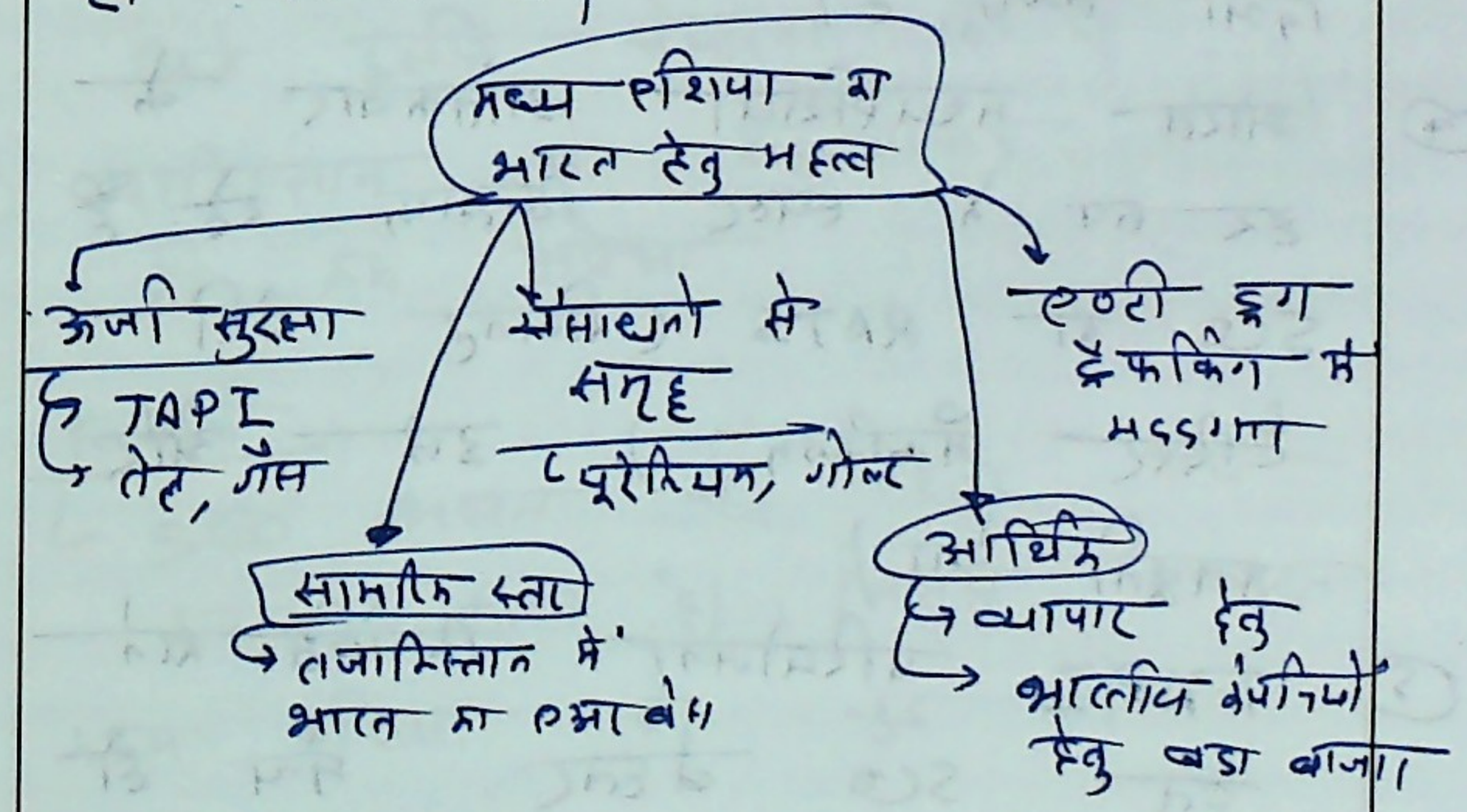

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

SCO कैसे मददगार

(1) हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाये गए। फलतः चाबाहार के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुंच सीमित हुई है। SCO हमें अन्य मार्ग उपलब्ध करायेगा।

(2) अफगानिस्तान से अमेरिका सुरक्षा बलों के जाने से वहाँ सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ, अस्थिरता बढ़ने से मध्य एशिया तक पहुंच प्रभावित होगी।

(3) गोल्डन क्रीसेंट से ड्रग्स दुर्व्यापार रोकने में SCO महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

(4) भारत - मध्यएशिया आतंकवाद के हर रूप के स्पष्ट खिलाफ रहे हैं। SCO का RATS (रीजनल एंटी टैरिरस्ट मैकेनिज्म) इसे और मजबूती देगा।

(5) TAPI परियोजना क्रियान्वित करने हेतु SCO बेहतर मंच हो

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

सकता है। क्योंकि पाकिस्तान भी SCO का ~~सं~~ सदस्य है। और पाकिस्तान ~~के~~ से संबंधों की पुर्नबहाली में SCO मददगार हो सकता है।

~~कुछ~~ इसके बावजूद कुछ चुनौतियाँ बनी रहेंगी।

① ~~SCO~~ चीन का मध्य एशिया से व्यापार 50 Billion $ से अधिक है जबकि भारत मात्र 2 बिलियन $ के स्तर पर

② SCO चीन, रूस केंद्रित है अतः भारत के हितों को ~~बाधित~~ संरक्षण मिले इसकी संभावना कम है

③ पाकिस्तान से सहयोगात्मक संबंधों की कम अपेक्षा

निष्कर्ष

↳ SCO भारत को बेहतर मंच प्रदान करता है। जिससे भारत मध्य एशिया से जुड़ सके

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

18. दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ाने में सार्क की विफलता ने क्षेत्रीय देशों को बिम्सटेक के रूप में एक व्यावहारिक विकल्प तलाशने हेतु प्रेरित किया है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

The failure of SAARC to nurture cooperation in South Asia has pushed regional players to explore BIMSTEC as a viable alternative. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

~~स~~ हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया गया अतः स्पष्ट है कि भारत ने अपनी नीति को सार्क के बजाय बिम्सटेक की ओर मोड़ना चाहता है।

दक्षिण एशिया में सार्क बेहद विफल रहा है। जैसे

① दक्षिण एशिया ~~सबसे~~ न्यूनतम एकीकृत क्षेत्र है। जहाँ कुल व्यापार का मात्र 5% व्यापार होता है।

SAARC	EU	ASEAN
5%	60%	45%

② साझा विश्वास की कमी

↳ पाकिस्तान और भारत के मध्य गतिरोध सबसे अहम है।

③ पिछले 33 वर्षों में मात्र 18 शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(4) सम्मेलन हेतु सभी देशों की अनुमति से इसके सम्मेलनों के आयोजन को रोका है।

(5) विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वसम्मति के चलते
- मोटर व्हीकल बिल लागू न हो पाया
- सार्क सैटेलाइट अधूरा

(6) SAFTA अभी भी क्रियान्वित नहीं।

अतः स्पष्ट है कि SAARC की विफलता ने हमें बिम्सटेक की ओर देखने को विवश किया है।

बिम्सटेक ~~निम्न लाभ प्रदान करते~~ से निम्न अवसर भारत को प्रदान करता है

(1) बिम्सटेक में कुल 7 देश है जिसमें 5 दक्षिण एशिया (पाक, अफगानिस्तान, मालदीव छोड़कर) तथा 2 आसियान देश (थाईलैण्ड, म्यांमार) है।

(2) ~~दक्षिण~~ भारत को आसियान देशों से जोड़ता है। तथा भारत की लुक ईस्ट नीति को क्रियान्वित करता

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

(3) पूर्वोत्तर में विकास में अहम भूमिका निभा सकता है।

(4) हालांकि इसके बावजूद विभिन्न में संस्थागत ~~के~~ स्तर पर प्रगति बहुत कम हुई है।

निष्कर्ष

पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता है अतः सभी के साथ हमें संबंधों को जुड़ा करके रास्ते खुले रखने चाहिए तब तक विभिन्न के माध्यम से हमें आगे बढ़ सकते हैं

उम्मीदवार को
हाशिये में नहीं
चाहिये।
(Candidate m
write on this

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

19. भारत के लिये क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर.सी.ई.पी.) का क्या महत्त्व है? विशेष रूप से चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये इसके निहितार्थ का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

What is the significance of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) for India? Examine its implications for the Indian economy especially in the context of free trade agreement with China. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

RCEP एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन है जिसमें कुल 16 सदस्य देश शामिल है

10 आसियान देश
- भारत
- चीन

जापान
द. कोरिया

आस्ट्रेलिया
न्यूजीलैंड

RCEP का सम्पूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था में 22% योगदान तथा व्यापार में 25% योगदान रखता है

भारत हेतु महत्व

(1) व्यापार संभावनाओं में वृद्धि होगी

(2) सेवाओं को भारत अग्रणी है अतः सेवा संबंधी प्रावधान भारत को फायदा पहुंचा सकते है

(3) निवेश संबंधी प्रावधान भारत में आसियान, चीन, जापान जैसे देशों का

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

निवेश गंतव्य बन सकता है।

इसके बावजूद RCEP में शामिल होने भारत हेतु कई अर्थों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

(1) चीन का सस्ता विनिर्मित माल भारत के बाजार को पाट सकता है।
L इससे भारत का घरेलू विनिर्माण तंत्र को चोट पहुंच सकती है।

(2) भारत का विनिर्माण उद्योग बेहद कमजोर अवस्था में है। वहीं आसियान और चीन जैसे देशों का विनिर्माण सेक्टर बेहद मजबूत है।

(3) चीन बड़ी मात्रा में सब्सिडी युक्त वस्तुएँ भारत में डंप कर सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation
उम्मीदवार को हाशिये में नहीं ... चाहिये। (Candidate mu... write on this m...)

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

निष्कर्ष

① RCEP में ~~भारत~~ भारत का शामिल होना लाभदायक हो सकता है किन्तु भारत को अपने हितों को ख्याल रखते हुए ही इस समझौते पर आगे बढ़ना चाहिए विशेषकर सेवा क्षेत्र में हमें अपनी स्थिति का लाभ उठाने का भरसक प्रयास करना चाहिए

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

20. निरंतर हठधर्मिता दिखाते चीन के साथ संबंधों को बनाए रखना भारतीय विदेश नीति की प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में उभरा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Dealing with an increasingly assertive China has emerged as one of the principal challenges of Indian foreign policy. Discuss in the context of China's growing influence in South Asian region. (250 words) 15

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं ... चाहिये। (Candidate m... write on this r...)

पिछले दशक में दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव में लगातार वृद्धि हुई है। जोकि निम्न रूप में देखा जा सकता है।

(1) पाकिस्तान
- CPEC का क्रियांवयन
- 50 Billion $ से अधिक निवेश
- ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से अरब सागर तक पहुच

(2) श्रीलंका
- हम्बनटोटा पत्तन लीज पर लिया
- ~~श्रीलंका~~ चीन समर्थक महिंदा राजपक्षे

(3) मालदीव
- ① कई द्वीप चीन को दिए गए
- ② महत्वपूर्ण परियोजनाओं भारत से छीनकर चीन को देना
  - एअर पोर्ट विकास GMR से छीन लिया गया

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

↳ पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन द्वारा चीन समर्थक नीतियों का पालन

नेपाल
↳ मधेशी विवाद (2015) के बाद चीन से नेपाल की नजदीकी बढ़ी
↳ सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश

बांग्लादेश
↳ बड़ी मात्रा में निवेश
↳ चीनी पनडुब्बियों की उपस्थिति

अतः स्पष्ट है कि चीन द्वारा अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रभाव में वृद्धि की गई। इसके बावजूद कई हठधर्मिता के बाद भी चीन के साथ संबंध रखने की हमारी जरूरत बनी हुई है।

हठधर्मिता
↳ (1) डोकलाम मुद्दे पर चीन की हठधर्मी नीति

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं ... चाहिये। (Candidate m... write on this r...)

(2) NSG में प्रवेश में बाधा।

(3) मसूद अजहर को आतंकी घोषित करवाने में कई बार बाधा डाली

(4) CPEC का PoK से गुजरना

इसके बावजूद मजबूत संबंध के कारण

(1) भारत का अहम पड़ोसी है। जिसके साथ हमारे सीमा विवाद भी

(2) आर्थिक → सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार → RCEP

(3) विभिन्न मंचों पर → SCO

इसके बावजूद भारत चीन को प्रतिसंतुलित करने हेतु अमेरिका से मधुर संबंधों में वृद्धि की है QUAD को अपनी भागीदारी को आगे बढ़ाया है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation